भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 2409

सोमवार, 10 अगस्त, 2026 (19 श्रावण 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान (आरसीएस-उड़ान) की स्थिति तथा पुनर्गठन

2409. डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः

श्री नरेश बंसलः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के आरंभ से अब तक प्रचालनरत किए गए असेवित तथा अल्प-सेवित विमानपत्तनों, हेलीपोर्टों तथा वाटर एयरोड्रोमों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विमान सेवा प्रचालकों को वर्ष-वार कुल कितनी व्यवहार्यता अंतराल निधि वितरित की गई, तथा उक्त अवधि के दौरान संचालित आरसीएस उड़ानों की कुल संख्या तथा सब्सिडीयुक्त हवाई किरायों से लाभान्वित यात्रियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संशोधित उड़ान ढांचे की कार्यान्वयन योजना का ब्यौरा क्या है, जिसमें इसकी कार्यान्वयन समय-सीमा, निधि आवंटन रणनीति तथा योजना के अंतर्गत विमानपत्तनों, हेलीपोर्टों एवं मार्गों की पहचान हेतु अपनाए गए चयन मानदंड शामिल हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): 'उड़ान' योजना के तहत, देशभर में 17 हेलीपोर्टों और 2 वॉटर एयरोड्रॉमों सहित 95 हवाईअड्डों को विकसित और कार्यशील किया गया है। दिनांक 10.07.2026 तक, 1.68 करोड़ से अधिक घरेलू यात्रियों ने 3.58 लाख आरसीएस उड़ानों में यात्रा की है। 'उड़ान' योजना के तहत कार्यशील किए गए हवाईअड्डों, हेलीपोर्टों और वॉटर एयरोड्रॉमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुलग्नक-I में संलग्न है। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान 'उड़ान' योजना के तहत एयरलाइनों को संवितरित किया गया व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।

(ग): देशभर में टियर-2 एवं टियर-3 शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 'उड़ान' योजना का अगला चरण दिनांक 04.07.2026 को शुरू किया गया है, जिसमें अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लक्षित किया गया है। इस योजना को 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक लागू किया जा रहा है, जिसमें 12,159 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मौजूदा असेवित हवाईपट्टियों से 100 हवाईअड्डों का विकास और पर्वतीय, पूर्वोत्तर एवं आकांक्षी (एचआईएनईआर) क्षेत्रों में 3,661 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 200 हेलीपोर्टों का विकास शामिल है।

यह योजना चैलेंज मोड फ्रेमवर्क प्रदान करती है, जिसके तहत राज्य सरकारें विकास के लिए एयरोड्रॉमों और हेलीपैडों को नामित कर सकती हैं। प्रस्तावों का मूल्यांकन बाधारहित भूमि की उपलब्धता, अवसंरचना के तैयार होने, तकनीकी और परिचालन व्यवहार्यता, यातायात क्षमता, सांविधिक मंजूरियों और राज्य सरकारों के समर्थन के आधार पर किया जाता है।

अनुलग्नक-I

'उड़ान' योजना के तहत कार्यशील किए गए हवाईअड्डों, हेलीपोर्टों और वॉटर एयरोड्रोमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों/वॉटर एयरोड्रोमों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2
2	अरुणाचल प्रदेश	3
3	असम	4
4	बिहार	2
5	छत्तीसगढ	3
6	दमन और दीव	1
7	गुजरात	8
8	हरियाणा	1
9	हिमाचल प्रदेश	6
10	झारखंड	2
11	कर्नाटक	7
12	केरल	1
13	लक्षद्वीप	1
14	मध्य प्रदेश	3
15	महाराष्ट्र	7
16	मणिपुर	2
17	मेघालय	1
18	नागालैंड	1
19	ओडिशा	4
20	पांडिचेरी (यूटी)	1
21	पंजाब	4
22	राजस्थान	3
23	सिक्किम	1
24	तमिलनाडु	1
25	उत्तर प्रदेश	11
26	उत्तराखंड	13
27	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	**95**

अनुलग्नक-II

वर्ष 2023 से आज की तारीख तक 'उड़ान' योजना के तहत एयरलाइनों को संवितरित किया गया वीजीएफ (रुपये करोड़ में)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वित्तीय वर्ष : 2023-24	वित्तीय वर्ष: 2024-25	वित्तीय वर्ष: 2025-26
आंध्र प्रदेश	20.93	6.76	-
अरुणाचल प्रदेश	31.79	14.95	28.93
असम	19.08	31.04	16.92
बिहार	-	-	10.30
छत्तीसगढ	31.38	2.04	4.31
दीव	-	-	24.87
गुजरात	42.13	64.42	31.80
हिमाचल प्रदेश	26.83	15.96	11.33
झारखंड	3.23	4.03	3.93
कर्नाटक	91.32	54.09	85.31
लक्षद्वीप	-	18.62	24.75
मध्य प्रदेश	35.93	1.89	15.78
महाराष्ट्र	21.29	96.64	172.92
मणिपुर	-	4.22	7.09
मेघालय	19.52	10.50	2.77
नागालैंड	3.56	5.01	-
ओडिशा	43.28	21.84	13.53
पंजाब	8.33	39.75	41.17
राजस्थान	14.55	40.95	55.39
सिक्किम	3.69	-	1.80
तमिलनाडु	6.29	22.87	27.66
उत्तर प्रदेश	120.10	121.18	56.25
उत्तराखंड	24.84	45.76	73.13
पश्चिम बंगाल	25.15	6.29	6.38
कुल	**593.23**	**628.80**	**716.31**

******